



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 383]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 1984/श्रावण 19, 1906

No. 383]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 1984/SRAVANA 19, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1984

का आ 592(अ)/18कक/आई डी आर 7/84 — भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश में का. आ. 617(अ)/18कक/आईडीआर/77 तारीख 12 अगस्त, 1977 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में सेमि इंडोर टेक्सटाइल लिमिटेड उज्जैन, मध्य प्रदेश नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के अधीन राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए गठन कर लिया गया था और उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया था

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश में का आ 566 (अ)/18कक/आईडीआर/82 तारीख 11 अगस्त, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को तारीख 11 फरवरी, 1983 तक की छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश में का आ. 103 (अ)/18कक/आईडीआर/83 तारीख 9 फरवरी, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को तारीख 11 अगस्त, 1983 तक की छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया गया था,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश में का आ 566 (अ)/18कक/आईडीआर/83 तारीख 9 अगस्त, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 11 फरवरी, 1984 तक की छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाई गई थी,

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश में का आ 83 (अ)/18कक/आईडीआर/84 तारीख 10 फरवरी, 1984 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 11 अगस्त, 1984 तक की छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाई गई थी,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकनिम में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम 11 फरवरी 1985 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, की छह मास की और अवधि के लिए मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के प्रबंध के अधीन बना रहना चाहिए,

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा पदतर्जनी का प्रयोग करने हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त

आदेश 11 फरवरी, 1985 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, को यह मामला को जी० आर० के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा. सं. 3 (1)/81-सी यू एम]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 10th August, 1984

S.O. 592(E)|18AA|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 617(E)|18AA|IDRA|77, dated the 12th August, 1977 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Indora Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh, was taken over under section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette, and the Madhya Pradesh State Textile Corporation Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E)|18AA|IDRA|82, dated the 11th August, 1982, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto the 11th February, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 103(E)|18AA|IDRA|83, dated the 9th February, 1983, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto the 11th August, 1983;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 566(E)|18AA|IDRA|83, dated the 9th August, 1983, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto the 11th February, 1984;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 83(E)|18AA|IDRA|84, dated the 10th February, 1984, the period of the said Order was extended for a further period of six months upto the 11th August, 1984;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Madhya Pradesh State Textile Corporation for the further period of six months upto and inclusive of the 11th February, 1985;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of

1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 11th February, 1985.

[F, No. 3(1)|81-CUS]

का आ. 593(अ)/18चख/आईडीआरए/84.—भारत सरकार, के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 105(अ)/18चख/आईडीआरए/78, तारीख 17 फरवरी, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी सविदाओं, 'सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, कगारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों' का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्व संबंधित हैं) जिनका मैसेज इंदौर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश नामक औद्योगिक उपयम एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपयम या कम्पनी को लागू हो, प्रवृत्त ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निरालिप्त रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निरालिप्त रहेंगे,

और उक्त आदेश की अवधि आदेश का. आ. सं. 79(अ)/18चख/आईडीआरए/79, तारीख 7 फरवरी, 1979, का. आ. सं. 89 (अ)/18चख/आईडीआरए/80, तारीख 28 फरवरी, 1980, का. आ. सं. 95(अ)/18चख/आईडीआरए/81, तारीख 13 फरवरी, 1981, का. आ. सं. 31(अ)/18चख/आईडीआरए/82, तारीख 16 फरवरी, 1982, का. आ. सं. 567(अ)/18चख/आईडीआरए/82, तारीख 11 अगस्त, 1982, का. आ. सं. 104(अ)/18चख/आईडीआरए/83, तारीख 9 फरवरी, 1983, का. आ. सं. 567/18चख/आईडीआरए/83, तारीख 9 अगस्त, 1983 और का. आ. सं. 84(अ)/18चख/आईडीआरए/81 तारीख 10 फरवरी, 1984 द्वारा समय समय पर 11 अगस्त, 1981 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान भी गया है कि उक्त आदेश की अवधि, 11 फरवरी, 1985 तक की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाए,

अतः, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि, 11 फरवरी, 1985 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है।

[फा. सं. 3(1)/81-सी यू एम]

ए० पी० सरस्वत, संयुक्त सचिव

S.O. 593(E)|18FB|IDRA|84.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 105(E)|18FB|IDRA|78, dated the 17th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settle-

ments, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Indore Textiles Limited, Ujjain, Madhya Pradesh is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And, whereas, the duration of the said Order was extended from time to time upto and inclusive of the 11th August, 1984, by the Orders No. S.O. 79(E)|18FB|IDRA|79, dated the 7th February, 1979, No. S.O. 89(E)|18FB|IDRA|80, dated the 8th February, 1980, No. S.O. 95(E)|18FB|IDRA|81, dated the 13th February, 1981, No. S.O. 31(E)|18FB|IDRA|82, dated the 16th February, 1982, No. S.O. 567(E)|18FB|IDRA|82, dated the 11th August, 1982, No. S.O. 104(E)|18FB|IDRA|83, dated

the 9th February, 1983, No. S.O. 567(E)|18FB|IDRA|83, dated the 9th August, 1983 and S.O. No. 84(E)|18FB|IDRA|84 dated the 10th February, 1984;

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 11th February, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 11th February, 1985.

[F. No. 3(1)|81-CUS]
A. P. SARWAN, Jr. Secy.

